नईदुनिया

भोपाल, 25 अगस्त 2026

खास-खबरें

केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर लगी रोक तत्काल प्रभाव से हटाई

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने गेहूं और इसके उत्पादों के निर्यात पर लगी रोक तत्काल प्रभाव से हटा दी है, जिसमें 'ड्यूरम' किस्म भी शामिल है। सरकार ने गेहूं के आटे और मैदा एवं सूजी जैसे अन्य उत्पादों के निर्यात की भी अनुमति दे दी है। डीजीएफटी की ओर से सोमवार को जारी अधिसूचना में गेहूं और इसके उत्पादों (जैसे आटा, मैदा, सूजी और ड्यूरम गेहूं) के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से हटाने की जानकारी दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि गेहूं की निर्यात नीति को तत्काल प्रभाव से 'प्रतिबंधित' की जगह 'मुक्त' श्रेणी कर दिया गया है। यह निर्णय देश में गेहूं के अच्छे स्टॉक और रिकॉर्ड उत्पादन को देखते हुए लिया गया है। अधिसूचना के मुताबिक इसके अलावा सरकार ने गेहूं के आटे और मैदा एवं सूजी जैसे अन्य उत्पादों के निर्यात की भी अनुमति दे दी है। केंद्र सरकार ने इस साल फरवरी में गेहूं के सीमित मात्रा में निर्यात की अनुमति दी थी। एचएस कोड 11010000 के तहत आने वाले गेहूं के आटे और उससे जुड़े उत्पादों की एक्सपोर्ट पॉलिसी को तत्काल प्रभाव से 'प्रतिबंधित' से बदलकर 'मुक्त' कर दिया गया है।

चुम्बकीय पंखे से मुफ्त बिजली का दावा

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: बिजली का बिल कम करने के लिए सौर पैनल और पवन टरबाइन जैसे विकल्पों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी बीच चुम्बकीय पवन टरबाइन को लेकर भी चर्चा हो रही है। इस तकनीक में चुम्बक की मदद से पंखे जैसी संरचना को घुमाने और उससे बिजली पैदा करने की बात कही जाती है। चुम्बकीय पवन टरबाइन में चुम्बकों और घूमने वाली संरचना का इस्तेमाल किया जाता है। इसका उद्देश्य हवा की गति से मिलने वाली ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है। सामान्य पवन टरबाइन की तरह इसमें भी हवा की गति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हवा के प्रभाव से पंखे या ब्लेड घूमते हैं और इस गति का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। चुम्बकीय व्यवस्था का उपयोग घर्षण कम करने और घूमने वाली प्रणाली की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। चुम्बकों के बीच आकर्षण और विकर्षण का इस्तेमाल घूमने वाली संरचना के संचालन में किया जाता है। हालांकि, केवल चुम्बक अपने आप लगातार बिजली पैदा नहीं कर सकते। बिजली उत्पादन के लिए किसी बाहरी ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है। हवा से मिलने वाली ऊर्जा ऐसी प्रणाली में प्रमुख स्रोत हो सकती है। घर के स्तर पर बिजली उत्पादन के लिए ऐसी तकनीक को लेकर लोगों की रुचि बढ़ रही है। इसका उद्देश्य पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम करना और बिजली के खर्च में कमी लाना है। हालांकि, किसी भी घरेलू ऊर्जा उपकरण की उपयोगिता उसकी क्षमता, हवा की उपलब्धता, स्थापना की जगह और बिजली उत्पादन की वास्तविक दक्षता पर निर्भर करती है। सौर पैनल की तुलना में पवन आधारित उपकरणों के लिए पर्याप्त हवा की उपलब्धता जरूरी होती है। इसलिए इन्हें हर स्थान पर समान रूप से प्रभावी नहीं माना जा सकता। चुम्बकीय पवन टरबाइन की तकनीक में भी वास्तविक बिजली उत्पादन हवा की गति और उपकरण की संरचना पर निर्भर करेगा।

निर्मला सीतारमण आज से कनाडा और अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक दौरे पर जाएंगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को मजबूत करना, निवेश के संबंधों को गहरा करना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग को आगे बढ़ाना होगा। वित्त मंत्रालय के मुताबिक केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री इस यात्रा के दौरान टोरंटो में कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री फ्रांस्वा-फिलिप शैम्पेन के साथ में पहले भारत-कनाडा आर्थिक और वित्तीय संवाद में भाग लेंगी और अमेरिका में जी-20 बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगी। कनाडा और अमेरिका की यात्रा के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रमुख निवेशकों, व्यवसायों और वित्तीय क्षेत्र के प्रतिनिधियों केसाथ गोलमेज चर्चा में भाग लेंगी और साथ ही निजी क्षेत्र के साथ उच्च-स्तरीय बातचीत भी करेंगी।

इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री अमेरिका की जी-20 अध्यक्षता के तहत होने वाली जी-20 एफएमसीबीजी बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगी। सीतारमण टोरंटो और शिकागो में रहने वाले भारतीय समुदायों से बातचीत करेंगी, ताकि लोगों के बीच आपसी संबंध और आर्थिक रिश्ते मजबूत हो सकें।

ईरानी रियाल 20 लाख प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर

अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच मुद्रा पर बढ़ा दबाव, तेल निर्यात और वित्तीय लेनदेन प्रभावित

तेहरान, एजेंसी: ईरान की मुद्रा रियाल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। अनियंत्रित बाजार में सोमवार को एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 20 लाख ईरानी रियाल दर्ज की गई। यह गिरावट ऐसे समय में आई है जब अमेरिका ईरान के खिलाफ नए और कड़े आर्थिक प्रतिबंधों की तैयारी कर रहा है। पिछले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बड़ी आर्थिक कार्रवाई की घोषणा के बाद रियाल में करीब 4.5 प्रतिशत की गिरावट आई है। अमेरिका का उद्देश्य ईरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करना है। इसके तहत ईरान के चुनिंदा कारोबारी साझेदारों को चेतावनी दी जा रही है। साथ ही फारस की खाड़ी में ईरान के प्रमुख बंदरगाहों पर नाकाबंदी और उसके विदेशी मुद्रा आय के प्रमुख स्रोत तेल निर्यात पर रोक लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

ईरान के केंद्रीय बैंक के गवर्नर अब्दोलनासर हेम्मती के अनुसार, देश का कच्चे तेल का निर्यात लगभग पूरी

तरह बंद हो गया है। ईरान के प्रमुख कारोबारी साझेदारों में शामिल संयुक्त अरब अमीरात ने भी अगले आदेश तक ईरान के साथ सभी वित्तीय लेनदेन रोक दिए हैं। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अमेरिकी कार्रवाई का उद्देश्य ईरानी व्यवस्था को चलाने वाली आर्थिक गतिविधियों को रोककर तेहरान को पूरी तरह अलग-थलग करना है। उन्होंने आर्थिक मोर्चे पर कार्रवाई को निर्णायक चरण की शुरुआत बताया है। ईरान के कारोबारी विश्लेषकों के अनुसार, विदेशी मुद्रा के हस्तांतरण में आ रही रुकावट, निर्यात में गिरावट, आयात की बढ़ती मांग और महंगाई की आशंका से मुद्रा संकट गहरा रहा है। ईरान से सबसे अधिक तेल खरीदने वाले चीन ने अमेरिकी आर्थिक दबाव का विरोध किया है और विवाद का कूटनीतिक समाधान निकालने की अपील की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि उनका देश चीन समर्थक साझेदार देशों के साथ व्यापार बढ़ाकर अमेरिकी दबाव का मुकाबला करेगा। रियाल के कमजोर होने से ईरान में रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं, दवाइयों और खाद्य पदार्थों की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। इससे महंगाई और अतिमुद्रास्फीति का खतरा भी बढ़ने की आशंका है।

देश में चीनी का पर्याप्त भंडार जल्द घट सकते हैं दाम

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: देशभर में चीनी की कीमतों में हालिया तेजी के बीच इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है। संगठन के अनुसार, आगामी त्योहारी सीजन की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आने वाले दिनों में खुदरा बाजार में कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। पिछले एक महीने में चीनी के दाम 20 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 56 से 60 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए हैं।

इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नीरज शिरगांवकर ने बताया कि कीमतों में हालिया वृद्धि के पीछे जमाखोरी और सट्टेबाजी के साथ मौसम संबंधी समस्याओं के कारण कम उत्पादन भी प्रमुख वजह है। उन्होंने कहा कि देश में आपूर्ति की बुनियादी स्थिति मजबूत है और त्योहारों के दौरान मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त चीनी मौजूद है।

चीनी के थोक और खुदरा बाजार में कीमतें बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने 20 अगस्त को 10 लाख टन कच्ची चीनी के बिना सीमा शुल्क आयात की अनुमति दी थी। इसका उद्देश्य घरेलू बाजार में आपूर्ति बढ़ाकर कीमतों को नियंत्रित करना है। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज ने भी देश में चीनी की उपलब्धता को पर्याप्त बताया है। संगठन के अध्यक्ष प्रकाश नाईकनवरे ने कहा कि वर्ष 2025-26 के लिए शुद्ध चीनी उत्पादन का अनुमान 2.79 करोड़ टन पर कायम है। इसमें से करीब 24 लाख टन चीनी

त्योहारों की मांग के लिए पर्याप्त स्टॉक, सरकार ने 10 लाख टन शुल्क-मुक्त कच्ची चीनी के आयात को दी मंजूरी

को इथेनॉल उत्पादन के लिए भेजा गया है। फेडरेशन के अनुसार, आयातित चीनी की कुछ खेप 15 अक्टूबर से पहले भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच सकती हैं। थाईलैंड में भी चीनी की कमी होने के कारण फिलहाल ब्राजील से आयात को विकल्प माना जा रहा है। ब्राजील से भारत तक जहाजों को पहुंचने में करीब 40 से 45 दिन लगते हैं। इसके बाद चीनी को मिलों तक पहुंचाया जाएगा। आयात की समयसीमा विदेश व्यापार महानिदेशालय की मंजूरी, साख पत्र और बंदरगाहों पर भीड़ जैसी स्थितियों पर निर्भर करेगी। नाईकनवरे ने कहा कि 31 अक्टूबर की आयात समयसीमा में छूट मिलने की संभावना है। जो खेप पहले से रास्ते में होंगी, उन्हें निर्धारित तारीख के बाद भी भारत आने की अनुमति मिल सकती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे तटीय राज्यों को आयातित कच्ची चीनी पहले मिलने की संभावना है। उत्तर भारत के राज्यों तक इसे रेल और सड़क मार्ग से पहुंचाया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुकूल कीमतें नहीं होने के कारण भारत ने 20 लाख टन के निर्धारित निर्यात कोटे में से केवल आठ लाख टन चीनी का निर्यात किया। फेडरेशन के अनुसार, प्रतिबंध नहीं होने की स्थिति में भी निर्यात 10 लाख टन से अधिक नहीं जाता। घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने 13 मई से 30 सितंबर तक चीनी के निर्यात पर रोक लगाई है।

लॉन्च से पहले दुकानों में दिखा गूगल का नया फिटनेस ट्रैकर

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: गूगल का नया फिटनेस ट्रैकर आधिकारिक लॉन्च से पहले ही दुकानों में नजर आया है। कंपनी इस उपकरण को अक्टूबर में लॉन्च करने की तैयारी में है। खास बात यह है कि इसमें स्क्रीन नहीं दी गई है। इसके बावजूद इसकी कीमत करीब 16 हजार रुपये बताई जा रही है।

नया फिटनेस ट्रैकर पहनने योग्य स्वास्थ्य उपकरण के रूप में पेश किया जाएगा। इसका उद्देश्य उपयोगकर्ता की दैनिक शारीरिक गतिविधियों और फिटनेस से जुड़ी जानकारी को दर्ज करना है। स्क्रीन नहीं होने के कारण इसमें सामान्य स्मार्टवॉच की तरह सीधे जानकारी देखने की सुविधा नहीं होगी। इसके लिए उपयोगकर्ता को जुड़े हुए स्मार्टफोन और संबंधित अनुप्रयोग पर निर्भर रहना होगा। स्क्रीनलेस डिजाइन के कारण उपकरण को हल्का और सरल रखा जा सकता है। इसे लगातार पहनने के लिए तैयार किया गया है, जिससे दैनिक गतिविधियों पर नजर रखने में सुविधा हो। फिटनेस ट्रैकर की मुख्य उपयोगिता इसके सेंसर और गतिविधि निगरानी क्षमताओं पर निर्भर करेगी।

यह उपकरण अक्टूबर में आधिकारिक रूप से बाजार में आने की तैयारी में है, लेकिन लॉन्च से पहले ही खुदरा दुकानों में इसकी मौजूदगी सामने आई है। इससे इसके बाजार में आने की प्रक्रिया शुरू होने के संकेत मिले हैं। करीब 16 हजार रुपये की कीमत में स्क्रीनलेस फिटनेस ट्रैकर का बाजार में आना इसे सामान्य फिटनेस बैंड और

स्क्रीन नहीं होने के बावजूद करीब 16 हजार रुपये कीमत

स्वास्थ्य गतिविधियों पर रखेगा नजर

स्मार्टवॉच से अलग श्रेणी में रखता है। उपयोगकर्ताओं के लिए इसकी कीमत और सुविधाओं के बीच संतुलन महत्वपूर्ण होगा। स्क्रीन की अनुपस्थिति का मतलब यह भी है कि ट्रैकर पर सूचनाएं, आंकड़े या अन्य जानकारी सीधे देखने के बजाय स्मार्टफोन के माध्यम से देखनी होगी। इससे उपकरण का डिजाइन अपेक्षाकृत सरल रह सकता है और इसका मुख्य ध्यान फिटनेस निगरानी पर केंद्रित होगा। अक्टूबर में आधिकारिक लॉन्च के बाद ही इसकी उपलब्धता, सुविधाओं और कीमत से जुड़ी पूरी जानकारी स्पष्ट होगी। फिलहाल दुकानों में इसके दिखाई देने से इसके बाजार में आने को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

पांच दिन बैंकिंग की मांग पर बैंककर्मी हड़ताल की तैयारी में

दो साल से लंबित है प्रस्ताव, 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: देशभर के बैंक कर्मचारी और अधिकारी सितंबर और अक्टूबर में हड़ताल पर जा सकते हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने सप्ताह में पांच दिन बैंकिंग व्यवस्था लागू करने और सरकार की नई प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन योजना वापस लेने की मांग को लेकर देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। मांगें नहीं मानी गईं तो 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी गई है।

बैंक यूनियनों का कहना है कि पांच दिन बैंकिंग का प्रस्ताव दो साल से अधिक समय से लंबित है। आठ मार्च 2024 को इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ हुए 12वें द्विपक्षीय समझौते और नौवें संयुक्त नोट में सप्ताह में पांच दिन बैंकिंग लागू करने पर सहमति बनी थी। प्रस्ताव के अनुसार, कर्मचारियों को सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन 40 मिनट अधिक काम करना होगा।

इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने प्रस्ताव को मंजूरी देकर केंद्र सरकार के पास भेजा था, लेकिन वित्त मंत्रालय से अब तक इसकी मंजूरी नहीं मिली है। वर्तमान व्यवस्था में बैंकों में महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश रहता है। पांच दिन बैंकिंग लागू होने पर सभी शनिवार को छुट्टी होगी और इसके बदले सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना कामकाज का समय 40 मिनट बढ़ जाएगा।

यूनियनों ने वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की ओर से जारी नई प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन योजना का भी विरोध किया है। उनका आरोप है कि योजना में कर्मचारियों के बीच भेदभाव किया गया है। स्केल चार और उससे ऊपर के अधिकारियों को व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर 365 दिनों तक के मूल वेतन के बराबर प्रोत्साहन मिल सकता है। वहीं, बैंककर्मियों और स्केल एक से तीन तक के कर्मचारियों के लिए अधिकतम 15 दिनों के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का प्रावधान है। यूनियनों का कहना है कि प्रोत्साहन योजना बैंक के समग्र प्रदर्शन पर आधारित होनी चाहिए और स्केल सात तक के सभी कर्मचारियों को समान दिनों का प्रोत्साहन मिलना चाहिए। उनका दावा है कि मौजूदा व्यवस्था इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और यूनियनों के बीच हुए समझौते के अनुरूप नहीं है।

प्रोत्साहन योजना का मामला मुख्य श्रम आयुक्त के समक्ष सुलह प्रक्रिया में लंबित है। इसे दिल्ली हाईकोर्ट में भी चुनौती दी गई है। यूनियनों ने द्विपक्षीय बातचीत के जरिए योजना में संशोधन की मांग की है।

सात हजार रुपये से कम में स्मार्ट ग्लासेज के विकल्प

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: स्मार्ट तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के बीच बाजार में ऐसे स्मार्ट ग्लासेज उपलब्ध हैं, जो कम कीमत में तकनीक और स्टाइल का संयोजन पेश करते हैं। सात हजार रुपये से कम कीमत वाले इन स्मार्ट ग्लासेज को रोजमर्रा के उपयोग को आसान बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

स्मार्ट ग्लासेज सामान्य चश्मे की तरह पहने जा सकते हैं, लेकिन इनमें तकनीकी सुविधाएं जोड़ी गई हैं। इनका उद्देश्य उपयोगकर्ता को बार-बार मोबाइल फोन देखने की जरूरत कम करना और कुछ जरूरी कामों को अधिक सुविधाजनक बनाना है। कम कीमत वाले विकल्पों की उपलब्धता से स्मार्ट ग्लासेज अब केवल महंगे तकनीकी उत्पादों तक सीमित नहीं रह गए हैं।

इन ग्लासेज में अलग-अलग मॉडल के अनुसार कई सुविधाएं मिल सकती हैं। इनमें फोन से जुड़ने की क्षमता, आवाज के जरिए कुछ कार्य करने की सुविधा और रोजमर्रा के उपयोग से जुड़ी तकनीकी खूबियां शामिल हो सकती हैं। कुछ मॉडल डिजाइन और पहनने के आराम पर भी ध्यान देते हैं, जिससे इन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सके। स्मार्ट ग्लासेज का उपयोग तकनीक और फैशन के बीच संतुलन बनाने के लिए भी किया जा रहा है। इनके डिजाइन सामान्य चश्मों की तरह रखे जाते हैं, ताकि इन्हें दैनिक जीवन में आसानी से पहना जा सके। इस वजह से ऐसे उत्पाद उन लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं, जो नई तकनीक के साथ अपने पहनावे में भी बदलाव चाहते हैं। बाजार में सात हजार रुपये से कम कीमत वाले स्मार्ट ग्लासेज की उपलब्धता से कम बजट में पहनने योग्य तकनीक अपनाने का विकल्प मिल रहा है। अलग-अलग मॉडल में मिलने वाली सुविधाओं और डिजाइन के आधार पर इनके उपयोग और अनुभव में अंतर हो सकता है।

सेंसेक्स 172 अंक टूटा, निफ्टी में भी गिरावट

बैंकिंग और मीडिया शेयरों में बिकवाली का दबाव, तीन नए आईपीओ खुले

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को गिरावट रही। सेंसेक्स 172 अंक टूटकर 77,369 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 33 अंक नीचे आकर 24,219 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान बैंकिंग और मीडिया क्षेत्र के शेयरों में अधिक बिकवाली देखने को मिली।

आज से तीन नए आरंभिक सार्वजनिक निर्गम खुले। सिम्बायोटेक फार्मालैब, हाई-टेक इंजीनियर्स और स्काईवेज एयर सर्विसेज के आईपीओ में निवेशक 26 अगस्त तक बोली लगा सकेंगे। सिम्बायोटेक फार्मालैब इस निर्गम के जरिए 1,757 करोड़ रुपये, हाई-टेक इंजीनियर्स 135.73 करोड़ रुपये और स्काईवेज एयर सर्विसेज 582.80 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है।

एशियाई बाजारों में भी सोमवार को

गिरावट रही। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 216 अंक गिरकर 6,697 पर बंद हुआ। जापान का निक्केई 488 अंक की गिरावट के साथ 65,528 और हांगकांग का हैंगसेंग 492 अंक टूटकर 25,517 पर बंद हुआ। इससे पहले 21 अगस्त को अमेरिकी बाजारों में तेजी रही थी। डाउ जोन्स 518 अंक बढ़कर 53,277 पर बंद हुआ था। नैस्डैक में 113 अंक और एसएंडपी 500 में 33 अंक की बढ़त दर्ज की गई थी।

घरेलू संस्थागत निवेशकों ने पिछले सात दिनों में भारतीय शेयर बाजार में 12,215 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे हैं। पिछले 30 दिनों में उनकी खरीदारी 39,757 करोड़ रुपये रही। विदेशी संस्थागत और पोर्टफोलियो निवेशकों ने सोमवार को 543 करोड़ रुपये की बिकवाली की, जबकि पिछले सात दिनों में उन्होंने 934 करोड़ रुपये और पिछले 30 दिनों में 8,464 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे हैं। इससे पहले 21 अगस्त को घरेलू शेयर बाजार में कारोबार लगभग सपाट रहा था। सेंसेक्स तीन अंक की बढ़त के साथ 77,540 पर और निफ्टी 20 अंक चढ़कर 24,252 के स्तर पर बंद हुआ था।

स्पेशल खबर नोमुरा की रिपोर्ट में दावा, अनुभवी कर्मचारियों की मांग बढ़ी; तकनीकी क्षेत्र में 90 प्रतिशत से अधिक नई नौकरियां

एआई से रोजगार के अवसर बढ़े, लेकिन नए कर्मचारियों की राह कठिन

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई को लेकर नौकरियां खत्म होने की आशंकाओं के बीच नोमुरा की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में एआई रोजगार खत्म करने की तुलना में नए अवसर अधिक पैदा कर रहा है। हालांकि, तकनीकी बदलाव का सबसे अधिक असर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के नए कर्मचारियों और शुरुआती स्तर के अभ्यर्थियों पर पड़ रहा है। भारत के साथ चीन और फिलीपींस में भी एआई के कारण रोजगार के अवसर बढ़ने की बात रिपोर्ट में कही गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, रोजगार बाजार में बदलाव को के-आकार का विभाजन कहा जा सकता है। एक ओर नए कर्मचारियों

और फ्रेशर्स की मांग घट रही है, जबकि दूसरी ओर अनुभवी और वरिष्ठ कर्मचारियों की जरूरत बढ़ रही है। कंपनियां अब ऐसे लोगों को प्राथमिकता दे रही हैं, जिन्हें प्रबंधन और कारोबार की गहरी समझ हो।

दक्षिण कोरिया के उन क्षेत्रों में भी इसी तरह का रुझान देखने को मिला है, जहां एआई का इस्तेमाल अधिक हो रहा है। कंपनियां बड़ी संख्या में पुराने कर्मचारियों को हटाने के बजाय नई नियुक्तियों की संख्या कम कर रही हैं। इसे शांत तरीके से कर्मचारियों की संख्या घटाने की प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। कॉलेज परिसरों में होने वाली नियुक्तियों में भी कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, एआई के कारण पैदा हो रहे नए रोजगार में 90 प्रतिशत से अधिक अवसर तकनीकी क्षेत्र में हैं। भारत में डेटा एनोटेशन, भाषा विज्ञान और एआई से जुड़ी सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में नई नियुक्तियां हो रही हैं। तकनीकी क्षेत्र के बाहर नए अवसरों की संख्या सीमित है। इनमें बैंकों में एआई जोखिम विश्लेषक और बिना चालक वाली गाड़ियों से जुड़े विशेषज्ञों जैसे पद शामिल हैं।

भारत की तुलना में चीन में एआई से जुड़े रोजगार का स्वरूप अलग है। वहां नई एआई प्रणालियां और मॉडल विकसित करने के लिए उच्च कौशल वाले स्नातकों की नियुक्ति अधिक हो रही है, जबकि भारत में समर्थन और सेवा आधारित रोजगार के अवसर अधिक दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, भारत के लिए आगे की राह चुनौतीपूर्ण है। देश लंबे समय से सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र के केंद्र के रूप में काम कर रहा है।

चोर के आते ही अपने आप जलेगी लाइट, घर की सुरक्षा का आसान उपाय

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: घर की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गति पहचानने वाली रोशनी एक उपयोगी और कम खर्च वाला विकल्प हो सकती है।

यह रोशनी आसपास होने वाली गतिविधि को पहचानकर अपने आप जल जाती है। इसका इस्तेमाल घर के प्रवेश द्वार, बरामदे, सीढ़ियों, गलियारे और अन्य ऐसे स्थानों पर किया जा सकता है, जहां रात के समय सुरक्षा की जरूरत अधिक होती है। गति पहचानने वाली रोशनी में सेंसर लगा होता है।

जो आसपास किसी व्यक्ति या वस्तु की गतिविधि का पता लगाता है। जैसे ही सेंसर को

गति पहचानने वाली रोशनी से अंधेरे में गतिविधि का तुरंत पता लगाने में मदद

हलचल महसूस होती है, रोशनी अपने आप चालू हो जाती है। कुछ समय तक गतिविधि नहीं होने पर यह अपने आप बंद भी हो सकती है। इससे रोशनी को लगातार चालू रखने की जरूरत नहीं पड़ती और बिजली की बचत भी हो सकती है। घर की सुरक्षा के लिहाज से ऐसी रोशनी को मुख्य दरवाजे या घर के बाहर आने-जाने वाले रास्तों पर लगाया जा सकता है।